# LOK SABHA DEBATES

## LOK SABHA

*Monday August 7, 1978/Sravana 16, 1900 (Saka)*

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[MR SPEAKAR *in the Chair*]

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Assistance to Small Farmers for Minor Irrigation

*304 SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether Government are considering the question of providing facility and assistance to small farmers in all the districts in the country for development of minor irrigation,

(b) the number of districts of Uttar Pradesh included under this scheme and

(c) how far this scheme will be successful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGTAION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) (a) Government of India have already decided to extend the facility of subsidy to small and marginal farmers for development of minor irrigation taken up on an area basis and with technical clearance in all areas of the country

(b) All districts of Uttar Pradesh will be covered under this;

(c) The Government of India's decision has been communicated to all the State Governments/Union Territories The implementation will be by the State Governments/Union Territories and their agencies As the benefits of minor irrigation to small and marginal farmers are realised by everyone, it is hoped that a large number of small and marginal farmers will be able to benefit under this scheme of assistance

**श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** मत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर मे उसी प्रश्न को पुन दोहरा दिया है। वास्तविकता उसमे क्या है, अर्थ क्या होना चाहिए, इसकी सच्चाई प्रकट नही होती है मत्री महोदय स्वय इस बात को स्वीकार करेगे कि आज राष्ट्रव्यापी सिचाई की एक बहुत बडी आवश्यकता है। चारो तरफ उसकी माग है और लघु सिचाई योजना के माध्यम से हम देश का कल्याण कर सकते है। जो योजना तैयार की गई है इसमे कितना धन व्यय किया जा रहा है? इस योजना को सभी राज्यो मे एक मापदण्ड के आधार पर लागू किया जायगा, इस विषय मे इन्होने कोई जानकारी नही दी, ये विस्तार से इस सदन को सूचित करे कि इसका स्वरूप क्या होगा?

आज तक मेरे जिले के अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई योजना लागू नही की गई है। उत्तर प्रदेश के मेरे जिले रामपुर मे केवल 30 प्रतिशत भूमि की सिचाई की व्यवस्था है, वहा पर छोटे छोटे किसान है, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की तरफ से आज तक कोई आर्थिक सहायता या लघु

सिंचाई योजना का कोई कार्यक्रम वहां नहीं दिया गया है, इस के क्या कारण हैं, मंत्री महोदय यह भी बतायें ?

**श्री भानु प्रताप सिंह :** समझने या समझाने में कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो सुविधा अभी स्माल फार्मर्स एजेन्सी वाले एरिया या स्पेशल प्रोग्राम वाले एरिया में उपलब्ध थी कि छोटे किसानों को सबसीडी मिलेगी, वह सारे देश के छोटे और मार्जिनल किसानों को उपलब्ध करा दी गई है। उसमें रामपुर जिला आता है। यह बात सही है कि अभी तक रामपुर जिले में कोई योजना ऐसी नहीं है, लेकिन जहां तक छोटे किसानों की सिंचाई की सुविधा का प्रश्न है, केवल रामपुर जिला ही नहीं, देश के हर जिले मे जहां नीचे पानी है, सिर्फ एक ही शर्त कि ग्राउन्ड वाटर की एवेलेबिलिटी है, इस बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद यह सबसीडी की सुविधा एक हैक्टर से नीचे वाले किसानों को 35 फीसदी, 1 से 2 हैक्टर वालों को 25 फीसदी और अगर कम्युनिटी, कई लोग मिलकर बनावें तो 50 फीसदी सबसीडी देश के सभी छोटे किसानों को जहां पानी उपलब्ध है, दिलायी गई है।

**श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे पूर्व स्माल फार्मर डेवलपमेंट एजेन्सी के नाम से देश के अनेक ब्लाक स्तर पर इस प्रकार की कई योजनाएं चलाई जा रही थीं। माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि जो तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके पीछे और कारण इन्वाल्व हो जाते हैं, उनके बारे में मंत्री विधायक या एम० पीज० प्रोपोजल देते हैं, वह योजनाओं को अपने-अपने क्षेत्र में ले जाते हैं, मेरा कहना यह है कि एक ही योजना सारे देश में सभी जिला स्तरों पर चलाई जानी चाहिए, इस बारे में भी मंत्री महोदय जानकारी दें ?

**श्री भानु प्रताप सिंह :** एक ही योजना सारे देश में एक साथ चलाना दो कारणों से संभव नहीं है। एक तो परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिए योजनाएं भिन्न-भिन्न बनानी पड़ेंगी, दूसरे आर्थिक साधनों की भी कमी है, किसी एक प्रोग्राम को पूरे देश में नहीं चला सकते। . . .

*(Interruptions)*

**MR. SPEAKER:** Parliamentary practice is that you must hear the Minister also, not merely put your questions.

**श्री भानु प्रताप सिंह :** यह बात जरूर है कि पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे इस के लिए हम लोगों ने गाइड-लाइन्स डेफाइन कर दी हैं कि किस प्रकार से यह ब्लाक छांटे जायेंगे।

**SHRI V. M. SUDHEERAN:** May I know from the hon. Minister whether he is aware of the grievances of the farmers of Kerala, particularly, of the Kuttanad area in Alleppey District and whether any representation has been received from the farmers in this regard for providing them assistance through the Kerala Government and if so, what is the reaction of the Government thereto?

**SHRI BHANU PRATAP SINGH:** If I remember correctly, I have visited that Kuttanad area and the farmers there gave me a representation. One of the demands was setting up a rice mill for processing the paddy produced in the Kuttanad area. . .

**MR SPEAKER:** We are on irrigation now. You may say if you have received any representation regarding irrigation.

**SHRI BHANU PRATAP SINGH:** As far as I am aware, no irrigation is required there. In fact, water has to be pumped out.

**MR. SPEAKER:** It is a question of draining there.

**श्री रामधारी शास्त्री** : मैं यह जानना चाहता हू कि सीमात किसानों को सब्सिडी के अलावा और सहायता देने की सरकार क्या योजना है ? क्या कृषि मत्रालय इस बात के ऊपर विचार करेगा कि जो छोटे किसान हैं उन को बैंक से जो ऋण मिलता हैं उस पर सूद की दर कम हो ?

MR. SPEAKER: That does not arise from the question This question relates to subsidy.

**श्री रामधारी शास्त्री** : मेरा क्वश्चन था कि सब्सिडी के अलावा और सहायता देने की इन की क्या योजना है ?

MR. SPEAKER: That again does not arise.

**श्री चन्द्रशेखर सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने जिलों में अभी तक यह योजना लागू की गई है और इस योजना के ऊपर कुल कितना पैसा खर्च हुआ ? दूसरा मेरा सवाल है कि क्या इस का कोई जिलेवार सर्वे कराया गया है कि कहां जमीन के नीचे पानी मौजूद है और कहां पानी मौजूद नहीं है ? जहा मौजूद नही है वहां पर सिंचाई के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

**श्री भानु प्रताप सिंह** : श्रीमन्, स योजना पर 40 6 करोड रुपया व्यय हुआ है और इस से लगभग 6 46 लाख किसानो ने लाभ उठाया है। ··(व्यवधान)·· सर्वे तो बराबर हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी।

**श्री चन्द्र शेखर सिंह** : कितने जिलो में अभी तक यह योजना लागू हुई है और क्या इस का कोई जिलेवार सर्वे किया गया है कि कहां कहा जमीन के नीचे पानी मौजूद है ? तीसरा मेरा सवाल है कि जहा पानी नही है जमीन के नीचे, वहा के लिए क्या योजना है ?

**श्री भानु प्रताप सिंह** : आन्ध्र प्रदेश मे 15, आसाम–4, बिहार–22, गुजरात–6, हरयाना-3, हिमाचल प्रदेश –3, जम्मू-काश्मीर–4, केरल–4, कर्नाटक–7, मध्य प्रदेश–12, महाराष्ट्र–12, मणिपुर–1, मेघालय–2, नागालैण्ड–1, उडीसा–7 पजाब–4, राजस्थान –6, त्रिपुरा–1, तामिलनाडु–12, उत्तर प्रदेश–26, वेस्ट बगाल–9, गोआ, दमन, ड्यू–1, पाडिचरी –1, दिल्ली–1, अरुणाचल प्रदेश–1 सिक्किम–1, इस प्रकार से इतने जिलो म यह लागू की गई है।

### Committee on Nationalisation of Irrigation Water Rates

*306 SHRI VASANT SATHE Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state in view of the wide disparity in the irrigation rates charged by the State Governments from the cultivators for important crops, would the Government consider setting up an experts committee task force to study the problem in depth and suggest rationalisation of water rates structures in the country which is most out-moded and highly un-economic?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) A statement is laid on the Table of the House

### Statement

Irrigation is a State subject and charges for supply of irrigation waters are fixed by the State Governments

Irrigation rates vary from State to State and sometimes within the State The question of rationalisation and uniformity of water rates has been engaging Government's attention over